were discussing the unemployment situation, the reply given to us was that Government had no knowledge about the total number of unemployed persons. Has the Committee been directed to assess the magnitude of the problem because in the absence of such an assessment, the Committee cannot serve any useful purpose?

SHRI R. K. KHADILKAR: The Committee is expected to have this assessment of the total magnitude of the problem.

MR. SPEAKER: It is a simple question and it has been discussed so many times during the last two weeks. Still members are asking questions.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: We are sitting on the top of a volcano.

MR SPEAKER: We had a discussion of it for so many hours.

Revision of Minimum Wages of Agricultural Labourers in Union Territories

*353. SHRI Y. ESWARA REDDY: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal to revise the minimum wages of agricultural labourers in Union Territories; and

(b) if so, the main features thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI BALGOVIND VERMA): (a) Government have published on 25th August 1972 for comments/suggestions draft proposals for the revision of the present minimum wages of agricultural labourers in respect of which the Central Government is the appropriate Government under the Minimum Wages Act, 1948.

(b) According to the draft proposals, the wages of the lowest category of workers (unskilled) which now range from Rs. 2.50 to 3.70 per day are proposed to be revised to a range from Rs. 3.00 to Rs. 4.50 per day, according to areas of employment.

SHRI Y. ESWARA REDDY: As per the Minimum Wages Act of 1948, we have to revise it every three years. May I know whether the Central Government have been discharging this responsibility, being the appropriate Government for the Union Territories? If not, what are the reasons therefor? Also, as far as I know, the States have not been doing this and the Centre which should have looked into it, have been keeping quite, unconcerned. Why?

SHRI BALGOVIND VERMA: The Centre has been discharging this responsibility. In 1969, we revised the wages Now we are going to revise them again. We have notified it in the gazette and are awaiting comments After that, it will be finally notified in the gazette.

SHRI Y. ESWARA REDDY: Even where the review was undertaken, the wages fixed by the States are below that required. Has any machinery been set up to implement the rates fixed because in many States such machinery has not been set up and they are not being implemented also?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI R. K KHADILKAR): It is a fact that some of the States are ignoring the general directions provided by the Centre while implementing our suggestions or recommendations.

SHRI MADHURYYA HALDAR: Which are these States?

SHRI R. K. KHADILKAR: Therefore, we are contemplating separate legislation in regard to agricultural labour.

SOME HON. MEMBERS *rose*—

MR. SPEAKER: My system of calling hon. members is: two blocks one, two blocks one, two blocks one. After all, they are also hon. members

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: They are more honourable than us.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: The former Speaker, Dr Sanjiva Reddy, used to follow this principle: one Opposition side, one the other side

MR SPEAKER In the normal practice you do get it.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: If you club this rule with that, they are all Congress members sitting there

MR SPEAKER: We are very sorry we miss him. There is another person sitting here now.

श्री नरसिंह नारायण पांडे : मंत्री महोदय ने कहा है कि बहुत से मुख्य मंत्रियो ने जो रिकोमेंडेशन्स है उनको इम्प्लेमेंट करने मे अपनी दिक्कतें बताई है। मैं जानना चाहता हू कि किन किन मुख्य मंत्रियो ने ये दिक्कतें बतायीं हैं और कौन सी दिक्कतें हैं जो जो उन्होंने बताई हैं ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : मध्य प्रदेश सरकार ने जो हमने नोटिफिकेशन किया उसके बारे मे अपनी कुछ परेशानियां बताई हैं उनके वहा पर वेज बहुत कम है। हम चाहते थे कि मिनिमम साढ़े चार होनी चाहिये। खास तौर पर दण्डकारण्य मे हम साढ़े चार करना चाहते। उन्होंने कहा कि हम इस स्थिति में नही हैं कि इतना दे सकें। अन्त में वे दो रुपया पचास पैसे देने पर राजी हो गये।

बिहार में भी कुछ जगह ऐसी ही हैं। बिहार गवर्नमेंट ने भी आपत्ति उठाई कि जो फिक्स की है उसको वे दे नहीं पायेंगे।

श्री हुकम चन्द कछवाय : बताया गया है कि कुछ राज्यो ने आपके निर्देश की उपेक्षा की है और कहा है कि हम इसको कर नहीं सकते हैं। उन्होंने अपनी कुछ दिक्कतें भी बताई है। मैं जानना चाहता हू कि कौन कौन से राज्य हैं जो आपके द्वारा बनाये गये नियमों का पालन करने मे कठिनाई का अनुभव करते है ?

आपने बताया है कि 2-50 और 3 रुपया मजदूरी देने का नियम बनाया गया है। देश के किसी भाग मे भी खेतिहर मजदूर को इतनी मजदूरी नही मिलती है। 18 या 20 रुपया महीना ही उसको तनख्वाह मिलती है। मैं जानना चाहता हू कि क्या आपने कोई मशीनरी बनाई हैं कि जो देख सके कि निर्धारित मजदूरी उनको मिल रही है या नही मिल रही है ? जो रिट आपने तय किया है वह अगर ठीक प्रकार से काश्तकार मजदूर के हाथ में नही पहुंचाता है तो उसके बारे में आप क्या कार्यवाई करने जा रहे है ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : जहां राज्य सरकार की एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है इसको एनफोर्स करने के लिये वहां हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जहां तक सेंट्रल स्फीयर की बात है जो हमने निश्चित किया है वह वहां पर दिया जाता है और यदि वहां पर कोई इस तरह की बात होती है और हमारे नोटिस में

आती है और हमे पता चलता है कि इतना पैसा नही मिल रहा है, तो उनके खिलाफ हम कार्यवाही करते हैं। जो चीज राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र मे होती है उसके बारे में हम कुछ नही कर सकते है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : खेतिहर मजदूर को 18 और 20 रुपये महीने की तनख्वाह मिलती है जब कि आपने 2-50 और तीन रुपया दैनिक तय की है। मैं आपको जानकारी दे रहा हू कि यह नही मिलती है। जो नही देते हैं उनके लिये सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : जो चीज राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र मे है, उसमे हम कुछ नही कर सकते हैं।

श्री हुकम चन्द कछवाय : इन लोगो की स्थिति बहुत खराब है, इनकी दशा दयनीय है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं..

अध्यक्ष महोदय : प्रार्थना भी होती है और भी कुछ हो जाता है। प्रश्न की प्रश्न ही रहने दिया करे।

श्री हुकम चन्द कछवाय : हम आपसे प्रार्थना ही कर सकते है ....

अध्यक्ष महोदय : प्रार्थना नही होती प्रश्न के साथ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : ये सत्ता लेकर बैठे हैं। सरकार इनकी है। मशीनरी इनके पास है. .

अध्यक्ष महोदय : इनका खयाल है कि ऊचा बोलने से या गडबड करने से रूल जाता रहता है। रूल मे यह है कि प्रश्न ही केवल कर सकते हैं। उन्होने कह दिया है कि हम कुछ नही कर सकते है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : यह गलत है इसके पास सत्ता है

अध्यक्ष महोदय : गलती मैं करता हूं जो आपको उठा देता हू।

श्री हुकम चन्द कछवाय : इनके हाथ मे सब कुछ है। राज्य सरकारो को ये आदेश दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपने कह दिया है जो कुछ आप कहना चाहते थे। अब हाउस का और वक्त जाया न करे।

SHRI VASANT SATHE May I know from the hon Minister whether in respect of agricultural labourers within your jurisdiction, in the union Territory, there is equal wage for both men and women employees? Secondly, what is the machinery for relating the minimum wage to the increasing prices so as to neutralise the rise in price by having some linkage with the index? Is there any such system? For three years you do not revise and in the meantime prices go up, the real minimum wage goes down. What are you doing to see that it is properly linked?

SHRI R K KHADILKAR Hon Members will realise that at the time of revision the attempt is to see that the proposal for revision reflects the rise in price. With all our efforts it is not always possible to ensure a minimum wage or need-based wage, let us be clear about it In this field

apart from the Government machinery. I should like to state very frankly that trade union leadership has completely and totally neglected the rural areas.

श्री सरजू पांडे : एग्रिकल्चरल लेबर जो गांवों में काम करती है उसकी दशा हमारे देश में सबसे ज्यादा खराब है। आपने रूल बनाया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप कोई मशीनरी फिक्स करने के लिये तैयार हैं ताकि वह देख सके कि जो भी कानून आप बनाते हैं उसका पालन होता है या नहीं और वह फालो अप एकशन ले सके? क्या केन्द्र की कोई जिम्मेदारी है इस मामले में या नहीं है कि उन कानूनों को वह लागू कराये? जो वर्कर उनके बीच काम करने जाते हैं और एजीटेशन करने जाते हैं उनकी अच्छी खासी पिटाई होती है, उनको इतना मारते हैं कि गांव में घुसने काबिल उनको नहीं रखा जाता है, इसके लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है? वहां पीसफुल मूवमेंट चलाना सम्भव नहीं है। अगर आपको गांवों का तिजुर्बा है तो आप भी इससे सहमत होंगे।

SHRI R. K. KHADILKAR: As has been already stated, the appropriate Government under the Constitution and the law in the State Government. Hon. members who are agitated about it should take it up with the State Government regarding the oppression or repression of the workers What can we do from here?

श्री सरजू पांडे : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अगर केन्द्रीय सरकार किसी कानून को बनाती है, तो उसको लागू करने के लिये उसको कोई मशीनरी भी बनानी चाहिये या नहीं?

SHRI VASANT SATHE: It is a concurrent subject. There is nothing to bar the Centre from making legislation which will over-ride the States.

श्री मूलचन्द डागा : जिन जिन राज्यों में अकाल की स्थिति है, वहां जो वर्कर्ज काम करते हैं, क्या उनके लिये मिनिमम वेजिज एक्ट लागू है या फैमिन कोड लागू है?

श्री बालगोविन्द वर्मा: वहां फैमिन कोड लागू होता है, मिनमम वेजिज एक्ट लागू नहीं होता है। यह तो उनको राहत देने की बात है। यह एक तरहसे ग्रेचुट्स रिलीफ है, जो ऐसे ही न देकर कुछ काम ले कर दिया जाता है।

SHRI MANORANJAN HAZRA: May I know how many States have adopted the Minimum Wages Act and the minimum and maximum rates in those States?

MR. SPEAKER. This is about Union Territories. You can give separate notice of this question.

SHRI B. N. REDDY: Why is the Central Government not able to ensure its implementation in the Union Territories....

MR. SPEAKER: He is not being called and he is forcing himself on me!

SHRI MANORANJAN HAZRA: My question has not been answered.

SHRI BALGOVIND VERMA: We have already stated that the Central Government is only competent to revise minimum wages in the case of these places where the Central Government is the appropriate Government. So far as the States are concerned, they are free to revise their minimum wages. We do not impose anything upon them. They do it themselves. I have got a long list as to which States have revised their minimum wages and which have not. I can read it if the Chair permits.

MR. SPEAKER: Next question.